पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 28, अंक 269 मार्च 2026

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश

तमसो मा ज्योतिर्गमय

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 28 अंक 269
मार्च 2026

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ.बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	03
2	भविष्यदर्शी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और आज की महिलाओं की स्थिति	बिकलेश कुमार गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर	04
3	जोधपुर जिले में मिर्च का घटता उत्पादन स्तर : एक विवेचना	डॉ. अश्वनी आर्य सुमल सोलंकी (शोधार्थी)	06
4	'नटनी' उपन्यास में वैचारिक प्रासंगिकता	डॉ. सुनील कुमार	08
5	Resisting Caste-based Discrimination through Dharma in Baburao Bagul's Bhohada	Niraj Raj Research Scholar Dr. Pramod Kumar Professor	11
6	The strategic Role of State Bank of India (SBI) in Financing Farmer Producer Organizations (FPOs)	Dr. Abhishikha Parmar	14
7	'ज़ख़्म अभी ताज़ा है'	सुरेन्द्र (शोधार्थी)	17
8	शिकंजे का दर्द में चरित्र- विन्यास और दलित यथार्थ	डॉ. नीतामणी बरदलै	20
9	Climate Change, Agricultural Value Chains and Greenhouse Gas Emissions in the Vidarbha Region of Maharashtra : A Review of Impacts, Emission Sources And Pathways for Resilience	Ravi N. Parmar Ph. D. Research Scholar Dr. Vitthal Kauthale, Ph. D. ,Chief Thematic Programme Executive	23

UGC Care Listed Journal

खाते का नाम - आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक - भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

आज हर एक को दूसरे का जीवन उजला और उल्लासमय लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। हम अन्तर्विरोधों से भरे समाज में जी रहे है, जहाँ हमें बोलने की आजादी तो है लेकिन हमारे पास आवाज नहीं है, चमक–दमक से भरे बाजार तो हैं लेकिन रूपया–पैसा नहीं है। बाजार के इस समूचे परिदृश्य में हमें एक बंधुआ महिला नजर आती है, लेकिन चमकती हुई। क्या यही स्वतंत्रता है?

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में भारतीय संविधान में लिंगभेद को नकारते हुए संविधान के अनुच्छेद 14–16, 23, 42, 44 और 46 आदि के द्वारा भारतीय महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार दिये गये हैं। फलस्वरूप भूमण्डलीकरण और उदारीकरण के दौर में 'वूमन लिबरेलाइजेशन' की दिशा में तेजी आई है। स्वतंत्रता, आर्थिक निर्भरता ने प्रगति के नये द्वार खोले हैं। कल्पनाओं की उड़ाने अंतरिक्ष तक पहुंच कर साकार होने लगी है। ''महिला सशक्तिकरण की राह पर चलकर उसने कुछ हद तक मंजिलों को पा भी लिया है। प्राचीन मान्यताओं को खण्डित कर वह अपनी अस्मिता को नई पहचान दिलाने में सफल भी हो रही है। आज नारी की समस्याएं ''अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार'' का विषय बन गई है।

वर्तमान सदी में महिला की स्थिति एवं विचारात्मक आन्दोलन है, जिसके साथ जुड़े हुए विचारों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सामान्य सिद्धांतों के संदर्भ में यह पुरुष के मुकाबले महिला की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से सरोकार रखती है। इस सदी में सारे संसार में महिलाओं को सशक्त बनाना तथा आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलम्बी बनाना है, परंतु विडम्बना यह है कि इस सदी के आरंभिक वर्ष ही महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न से भरे हुए है। आज महिलाएं न तो घर में सुरक्षित है और न ही बाहर।

एक समाचार के अनुसार हाल के वर्षों में इरान में महिलाओं ने कठोर कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में विरोध–प्रदर्शन किया। उनके आंदोलन को दुनिया भर में 'वूमन लाइफ, फ्रीडम' के नाम से जाना गया। वैश्विक स्तर पर इस पर चर्चा हुई। महिलाएं सड़कों पर उतरी, खुलकर अपनी बात रखी और विरोध में हिजाब उतार दिये। उनमें से कई ने असाधारण साहस दिखाया, जबकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा था कि इसके क्या खतरे हो सकते है। कई महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, कुछ को धमकियां मिली, कुछ को देश छोड़ना पड़ा और कुछ को स्वतंत्रता की मांग करने के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी।

भारत की महिलाओं को ये घटनाएं चौंकाने वाली लग सकती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जहां महिलाओं को अन्य देशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है।

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संघर्ष समाप्त हो गया है। भारत में आज भी दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, असमान वेतन और महिलाओं की पसंदगी पर सामाजिक दबाव जैसी समस्याओं के अलावा लाखों की तादाद में बालिकाओं व महिलाओं के लापता होने जैसी समस्याएं मौजूद है। वे अब भी आर्थिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा, घर व कार्यस्थल दोनों जगह समान सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम किन स्वतंत्रताओं को स्वाभाविक मानकर चल रहे हैं?

अब हमें एक नया रास्ता ढूंढ़ना होगा, हमें चीजों की तह तक जाना होगा। जब भी कभी सत्ता या सत्ताधारी मुक्ति की बात करते हो तो हमें चौकन्ना होकर उनकी बात सुनना–समझना चाहिए। यदि बहुत महिनता के साथ स्थिति की तह में जाएं, तो यह मुक्ति के नाम पर एक घेरा बना रहे होते हैं, जिसमें वे हंसकर आशीर्वाद की मुद्रा में महिला को बिठा रहे होते हैं।

वैश्वीकरण के इस दौर में राष्ट्र की प्रगति एवं विकास हेतु महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। जिसके लिए कानून और शासकीय कोशिशों के साथ ही जनसामान्य की सहभागिता जरूरी है। लड़के और लड़कियों को स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति तथा समाज और देश के प्रति जिम्मेदार बनना होगा।

बालिका सुशिक्षित, बालक जिम्मेदार और हम स्वयं बेहतर और संवेदनशील नागरिक बन सके तो महिलाएं स्वयं विकास कर सशक्त हो जाएंगी। और महिला सशक्त होती है, खुशहाल होती है तो राष्ट्र भी सशक्त होता है, खुशहाल व समृद्ध हो जाएगा। आईये हम सब मिलकर इसे चरितार्थ करें। अन्तर्राष्ट्रीय महिला–दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामना।

– डॉ. तारा परमार

भविष्यदर्शी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और आज की महिलाओं की स्थिति

– बिकलेश कुमार गुप्ता
असिस्टेंट प्रोफेसर

सारांश

भारत के संविधान में महिलाओं से संबंधित अधिकार जो उन्हें प्राप्त हुए हैं जिसका प्रयोग करके आज की महिलाओं ने अपनी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन करके समाज में एक अनूठी प्रस्तुति की है। सही मायने में यह परिवर्तन संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। बाबा साहेब, उस दौरान घटित घटनाओं से तथा समाज में फैली कुरीतियों को देखकर अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिए व आज की नारियां जो उस पुरातन परंपरा में फंसी हुई थी चार दीवारों में घिरी हुई थी लेकिन आज अंतरिक्ष में जा पहुंची है। यह है बाबा साहब अंबेडकर की संविधान की ताकत जो समाज में रहने वाली समस्त नारियों के लिए एक प्रकार का शक्तिशाली हथियार साबित हो रहा जिनका प्रयोग करके समाज की महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वाभिमान से जीवन यापन कर रही हैं।

कीवर्ड्स – महिलाएं, कानूनी, संविधान, बाबा साहब ।

शोध लेख

महिलाएं समाज की एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। जहां पर आने वाली पीढ़ी का सृजन होने वाला हो महिलाओं के द्वारा ही ऐसे परिवेश–क्षेत्र का निर्माण संभव हो सकता है। जिस क्षेत्र में उनकी योग्यता, सहनशीलता और महत्वपूर्ण सुझावों को समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार हो और महिलाओं को भी बोलने का, अपनी बात प्रस्तुत करने का अधिकार हो, तो हम उस समाज में खुशहाली को आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि समाज में पुरुष–महिला ही ऐसे सामाजिक प्राणी है जो इस मानव के सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने वंश को बढ़ाता है वह अकेले यह नहीं कर सकता। जब तक नारी जाति न हो। हजारों सालों से चली आ रही यह संसार भी इनके बिना अधूरी के समान है। माता, बहन, पत्नी और न जाने कितने रूपों में अपने कर्तव्य को निर्वाह करती है। लेकिन प्राचीन समय में स्त्रियों को उतनी स्वालंबन नहीं होगी, जितनी आज है। बल्कि महिलाओं से संबंधित कुरीतियां, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, घरेलू स्थिति दयनीय थी। कई आक्रांताओं के शासनकाल हिंसा, दहेज प्रताड़ना, जात–पात, छुआछत, अपनी उम्र से बड़े उम्र के पुरुष के साथ विवाह कर देना, महिलाओं को बेच देना, बेटियों को मार देना, और न जाने कितनी अनगिनत कष्ट–दुष्ट समाज के वातावरण में झेलना पड़ा होगा, हमने पुराने अध्ययनों को देखा जाना की महिलाओं को बोलने का, अपनी राय अपने समाज तक प्रस्तुत करने का पढ़ने–लिखने तक की आजादी नहीं थी। यदि स्त्रियां अपनी बातों को या विचारों को प्रस्तुत करती तो उन्हें ना समझ कह कर चुप कर दिया जाता था। महिलायें लोक लाज एवं समाज के दबाव के कारण भी अपनी बातों को किसी से कहने से घबराती थी। लेकिन अब यह 'बाबा साहब' का संविधान उन नारियों के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं को उस पुराने कल तक ही छोड़ने के लिए विवश कर दी है, जो एक युग में होती थी। आज उन्हें भी पुरुषों के साथ मुकाबला करने के लिए अवसर दे रही है। बाबा साहब ने महिलाओं की स्थितियों, स्वयं छुआछूत की घटनाएं, जातिवाद को अपने समय में देखें और उनके मन में केवल किसी एक धर्म, जात, समुदाय के लिए यह विचार नहीं था, जिस प्रकार से एक कुंठित व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ को ही देखता है। जिससे उसकी मानसिकता छोटी हो जाती है और वह अपने सिवा किसी अन्य को आगे बढ़ने के लिए अवसर नहीं देता, किंतु डॉ भीमराव अंबेडकर अपना अध्ययन उन महानगरों देश–विदेश में किए जहां पर जात–पात, छुआछूत, असामानता,

लड़कियों–लड़कों के साथ स्वतंत्रतापूर्वक बात करना, इन सभी को देखकर बाबा साहब ने महिलाओं को और पुरुषों को सदैव समानता की दृष्टि में रखने की बात करते थे एवं अपना निर्णय महिलाओं के प्रति हमेशा सहयोगात्मक रखे उन्होंने समस्त धर्म को समस्त जातियों के समुदायों की महिलाओं की स्थिति को देखते हुए अपने विचार को कानूनी रूप से मजबूती प्रदान की। इसलिए, उन्होंने महिलाओं के अधिकार को संविधान में शामिल करके महिलाओं से संबंधित समस्याओं और उनके निवारण को समाज तक पहुंचाने का कार्य किया। समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, नौकरियों में समानता, आरक्षण, यह सारे अधिकार केवल पुरुषों के लिए, नहीं बल्कि उन सारी स्त्रियों के लिए, हैं। जो किसी भी वर्ग विशेष से आती हो। हिंदू धर्म में होने वाली कुरीतिया से महिलाएं, किस प्रकार से प्रभावित थी। इसलिए, उन्होंने हिंदू कोड बिल भी लाये, किंतु दुर्भाग्यवश उस वक्त पारित नहीं हो सका, जिससे आहत होकर उन्होंने कानून मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया, अर्थात समाज के लिए और समाज के उन वंचित महिला पुरुष के प्रति उनका इतना स्नेह था जिनके आगे कोई पद का मोह नहीं रहा । मैं अपने कार्यस्थल जाने के लिए प्रत्येक दिन सफर करता हूं तो रास्ते में देखता हूं कि गांव की रहने वाली छोटी बेटियां साइकिल से अपने छोटे भाई को बैठाकर प्राथमिक विद्यालय में स्कूल ले जाते हुए, दिखती है, महिला और पुरुष सरकार द्वारा संचालित रोजगार गारंटी योजना में काम करने के लिए, और काम करते हुए, देखी जाती हैं, महिलाएं, और बेटियां बड़ी–बड़ी कार को ड्राइव करती हुई देखी जाती हैं, व्यावसायिक दुकानों में महिलां, दुकान संचालित करती हुई दिखती है, चूंकि मेरा मैनपाट क्षेत्र अपनी प्रकृति की खूबियों से भरी हुई है। जहां पर आदिवासी जनजाति समुदाय निवास करते हैं वहा सभी महिलाएं खेती–बाड़ी में मिल–जुल कर काम करते हुए, दिखती हैं। ग्राम क्षेत्र से लेकर एक सामुदायिक भवन चिकित्सालय तक नर्स से लेकर महिला डॉक्टर अपनी सेवा करते हुए, देखी जा सकती हैं। यह सारे दृश्य मुझे और किसी भी व्यक्ति को आनंदित करने के लिए, पर्याप्त है। क्यूंकि हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं, आज बड़े–बड़े क्षेत्र में चाहे वह उद्योग हो व्यवसाय, नौकरी, या हवा में उड़ने वाला लड़ाकू विमान हो, भूमि पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन हो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं का आज जो कर्तव्य दिख रहा है। उन सब के पीछे बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान उन्हें अवसर दे रहा है। प्रसिद्ध विद्वान विकास दिव्यकीर्ति अपने एक उद्‌बोधन में कहते हैं कि "महिला, आज पुरुषों की बराबरी कर रही है उनका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर को ही जाता है और वह नहीं होते तो आज महिला, भी शिक्षित नहीं हो पाती" बाबा साहब कहते है कि "शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा" आज तो हम देखते हैं कि परिवार के पति – पत्नी दोनों मिलकर कमाने का कार्य करते हैं। यह उस परिवार में ही देखने को मिल सकता है। जो स्त्री और पुरुष में बालक और बालिका में भेद न करता हो। यह उस समय संभव हो सकता है। जबकि परिवार का सहयोगात्मक रवैया अपने घर की स्त्रियों के प्रति हो, उनमें पूर्ण विश्वास हो, आज बहुत सारे प्रशासनिक पद को महिलाएं संभाल रही है। कहीं ना कहीं उस शिक्षित, परिवार का उनका सहयोग उनके साथ लगा हुआ है। ग्राम क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र तक महिलाओं को बच्चों को पढ़ने–पढाने का अवसर बाबा साहब अंबेडकर का यह संविधान प्रदान कर रहा है।

निष्कर्ष

उपयुक्त शोध लेख के अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि महिलाओं को भी इस समाज में आगे बढ़ने का अवसर मिलते रहना चाहिए, ताकि उनके भी विचार समाज के प्रत्येक वर्ग को प्राप्त होता रहे, डरा धमकाकर विचारों को कुचल देना कहीं ना कहीं हमारी निम्न सोच वाली मानसिकता को दर्शाती है। यह कब तक सफल हो सकता है केवल एक निश्चित सीमा तक उसके पश्चात यह उपयोगी नहीं हो सकती, आज समाज में रहने वाली किसी भी वर्ग विशेष से आने वाली महिलाएं क्यों ना हो सभी आगे बढ़ रही हैं। यह सब

बाबा साहब के दूरदर्शिता अर्थात भविष्यदर्शी का ही परिणाम रहा है। यदि समाज का प्रत्येक परिवार में शिक्षा का सही रूप हो और समानता की बात हो तो निश्चित रूप से बाबा साहब की इस सपने को पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकता और महिलाओं से संबंधित होने वाली अप्रिय घटना गांव से लेकर शहर तक कभी नहीं हो पाती।

– **बिकलेश कुमार गुप्ता**
असिस्टेंट प्रोफेसर
गवर्नमेंट नवीन कॉलेज मैनपाट, सरगुजा (छत्तीसगढ़)
HOD ऑफ पोलिटिकल साइंस
पोस्ट भिटीकँला जिला सरगुजा–497001
मोबा. 8319120319

संदर्भ :

1. मैं भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूं, श्री दिनकर कुमार प्रभात प्रकाशन 2024
2. बिकलेश कुमार गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट नवीन कॉलेज मैनपाट सरगुजा, छत्तीसगढ़
3. ब्राहमण कि बेटी– शरत चंद्र चट्टोपाध्याय प्रकाशन वर्ष 2024 प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
4. https://youtu-be/ALuyrcNjNRM\si=bpCS-kOBa47ohlP
5. https://gauravshalibharat-com/indian&woman/
6. https://hindiamrit-com/bhartiy-samaj-me-nari-ka-sthan-par-nibandh/
7. https://www-drishtiias-com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/status-of-women-in-india
8. दलित नारी का संवेदना का दस्तावेज सुमंगली– डॉ. जयश्री ओ. आश्वस्त पत्रिका (नवंबर 2024) संपादक डॉ. तारा परमार।
9. भारतीय लोकतंत्र के दीर्घ दृष्टिकर डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र –डॉ.मगन भाई मकवाना आश्वस्त पत्रिका (नवंबर 2024) संपादक डॉ तारा परमार

जोधपुर जिले में मिर्च का घटता उत्पादन स्तर : एक विवेचना

– **डॉ. अश्वनी आर्य**
– **सुमन सोलंकी**
(शोधार्थी)

सारांश

राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित जोधपुर जिला परम्परागत रूप से मिर्च उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्रस्तुत लेख में जोधपुर जिले में वर्ष 2013–14 से 2023–24 की अवधि में मिर्च उत्पादन बुवाई क्षेत्र, मिर्च उत्पादन, उत्पादकता का विश्लेषण द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मिर्च के बुवाई क्षेत्र में परिवर्तन, कुल उत्पादन में उतार–चढ़ाव तथा प्रति हेक्टेयर का मूल्यांकन करना है।

मुख्य शब्द : जोधपुर जिला, मिर्च उत्पादन, उत्पादकता, कृषि विकास।

परिचय

मिर्च की खेती राजस्थान ही नहीं वरन् सम्पूर्ण भारत में एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जो देश की अर्थव्यवस्था और विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मिर्च खरीफ के मौसम में जून – जुलाई में बोयी जाती है तथा सितंबर–अक्टूबर में काटी जाती है। जबकि रबी के मौसम में अक्टूबर–नवंबर में बोयी जाती है और मार्च–अप्रैल में कटाई की जाती है। राजस्थान में मुख्यतः मिर्ची बुवाई खरीफ (मानसून) के समय की जाती है परंतु इसकी कटाई का समय राज्य के अलग–अलग क्षेत्रों के वातावरण पर निर्भर करता है।

भारत में सालाना लगभग 1.3 से 1.5 मिलियन टन मिर्च का उत्पादन होता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ताजा और सूखे रूप में घरेलू स्तर पर खपत किया जाता है, जबकि पर्याप्त मात्रा में निर्यात भी किया जाता है। मिर्च गर्म, आर्द्र जलवायु में पनपती है। मिर्च की खेती के

लिए आदर्श तापमान सीमा 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मिर्च को पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है और यह पाले के प्रति संवेदनशील होती है। प्रति वर्ष 800–1200 मिमी वर्षा पर्याप्त है, लेकिन अत्यधिक नमी या सूखा विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मिर्च के सफल उत्पादन के लिए, अच्छी जल निकासी, पीएच 6.0–7.5, और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का उपयोग करने के साथ उचित सिंचाई व्यवस्था जिसमें जलभराव न हो और उसके लिए ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना और समय पर रोपण (नर्सरी के लिए अक्टूबर–नवंबर, फरवरी – मार्च में रोपाई करना आवश्यक है।

अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में हों, आदर्श है। फर्टिलाइजर के अनुसार, मिट्टी का आदर्श रूप से 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मिर्च 20–30 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में सबसे अच्छी तरह से उगती है। लंबे समय तक 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक या 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान से विकास और उपज प्रभावित हो सकती है। फलों के पकने के दौरान शुष्क परिस्थितियाँ गुणवत्ता के लिए फायदेमंद होती हैं।

पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा और शुष्क जलवायु होने के कारण यहां मिर्ची उत्पादन हेतु ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान का जोधपुर जिला मिर्ची उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र रहा है। राजस्थान में गर्म और शुष्क जलवायु होती है, इसलिए मिर्ची किस्मों का चयन करते समय ऐसी किस्म का चयन किया जाता है जो उच्च तापमान और सूखे की स्थिति को सहन कर सकें। अत्यधिक गर्मी के दौरान छाया या अन्य सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करना आवश्यक है।

जोधपुर जिले का भौगोलिक स्वरूप

जोधपुर जिला राजस्थान राज्य के सबसे बड़े जिलों में से एक है। यह राज्य के पश्चिमी भाग के मध्य में स्थित है और इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 22850 वर्ग किलोमीटर है। जोधपुर जिले का विस्तार 26^0 से $27^0 37'$ उत्तरी अक्षांश और $72^0 55'$ से $73^0 52'$ पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जिले की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई लगभग 197 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 208 किलोमीटर है। जोधपुर जिला समुद्र तल से 250–300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जिले का कुल क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है।

जोधपुर जिला राजस्थान राज्य के शुष्क क्षेत्र में आता है। यह राज्य के कुल शुष्क क्षेत्र का 11.60 प्रतिशत भाग है । भारत के विशाल थार रेगिस्तान का कुछ हिस्सा भी इस जिले में शामिल है। जिले में कोई बारहमासी नदी नहीं है और वर्षा जल के अलावा सिंचाई के मुख्य स्रोत कुएँ और ट्यूबवेल हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जिले में पेयजल का मुख्य स्रोत है। जिले की मिट्टी मुख्य रूप से बलुई और दोमट है। खरीफ ऋतु में बाजरा मुख्य फसल है

जोधपुर जिले में मिर्ची उत्पादन

जोधपुर जिले में वर्ष 2013–14 से 2023–24 मिर्ची की बुवाई क्षेत्रफल में बहुत कमी दर्ज की गई है। जहां वर्ष 2013–14 में मिर्ची बुवाई क्षेत्रफल 1107 हैक्टर था जो वर्ष 2023–24 में घट कर आधे से भी कम 415 हैक्टर रह गया। इस प्रकार चयनित अवधि में बुवाई क्षेत्र में कुल 692 हैक्टर की कमी दर्ज की गई।

जोधपुर जिले में वर्ष 2013–14 से 2023–24 मिर्ची के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है। जहां वर्ष 2013–14 में मिर्ची उत्पादन 538 टन था जो वर्ष 2023–24 में घट कर आधे से भी कम 245 टन रह गया। चयनित अवधि में जोधपुर जिले में मिर्ची उत्पादन

के लगातार उतार–चढ़ाव दर्ज किया गया ।

जोधपुर जिले में मिर्ची की उत्पादकता (कि.ग्रा./है.) में वर्ष 2013–14 से 2023–24 कमी दर्ज की गई है। जहां वर्ष 2013–14 में मिर्ची उत्पादकता 486 (कि.ग्रा./है.) थी जो वर्ष 2023–24 में बढ़ कर 590 (कि.ग्रा./है.) हो गई। इस प्रकार जोधपुर जिले में मिर्ची उत्पादन की उत्पादकता में कुल 104 कि.ग्रा/हैक्ट की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि जहां जोधपुर जिले में मिर्ची की उत्पादकता (कि.ग्रा./है.) में बढ़ोतरी हुई लेकिन दूसरी तरफ मिर्ची बुवाई और उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की जा रही है जिसका मूल कारण लगातार घटते जल स्तर को माना जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2013–14 में मिर्ची उत्पादन 538 टन था जो वर्ष 2023–24 में घट कर आधे से भी कम 245 टन रह गया। इसी प्रकार प्रति हैक्टर मिर्ची उत्पादकता वर्ष 2013–14 में 486 कि.ग्रा./हैक्टर की तुलना में वर्ष 2023–24 में बढ़ कर 590 कि.ग्रा./हैक्टर हो गई जिससे स्पष्ट है कि जोधपुर जिले में चयनित अवधि में प्रति हैक्टर उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद भी मिर्ची उत्पादन में कमी दर्ज की गई है।

– **डॉ. अश्वनी आर्य**
'सहायक आचार्य, भूगोल विभाग,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

– **सुमन सोलंकी**
"शोधार्थी,
जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

'नटनी' उपन्यास में वैचारिक प्रासंगिकता

– **डॉ. सुनील कुमार**

रत्नकुमार सांभरिया हिंदी कथा–साहित्य के उन प्रमुख कथाकारों में से हैं, जिन्होंने लगातार हाशिए पर पड़े, शोषित और घुमंतू समुदायों के जीवन को केंद्र में रखकर लेखन किया है। उनकी रचनाएँ दलित–विमर्श, स्त्री–चेतना, सामंती शोषण और सामाजिक अन्याय की गहन पड़ताल करती हैं। 'नटनी' (सेतु प्रकाशन, नोएडा, 2025) उनका दूसरा प्रमुख उपन्यास है, जो खानाबदोश नट जाति के जीवन, संस्कृति, शोषण और प्रतिरोध को साहित्य की मुख्यधारा में लाने का साहसिक प्रयास करता है। कथानक नट समाज की नायिका रज्जो (रज्जो उर्फ रीतासिंह) के इर्द–गिर्द बुना गया है, जो सामंती व्यवस्था, जातीय अहंकार, लिंग–भेद और आर्थिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष करती है। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में रज्जो का पति शमशेर सिंह, सास शीतलदेवी (इंसानियत और करुणा की जीती–जागती तस्वीर) तथा ससुर जिगर सिंह (सामंतवाद का प्रतीक) शामिल हैं। शमशेर सिंह का रज्जो पर प्रेम जातीय बंधनों को तोड़ने की दिशा में एक नया युग आरंभ करता है। उपन्यास की वैचारिक प्रासंगिकता आज के भारत में बहुआयामी है–यह हाशिए के घुमंतू समुदायों की आवाज बनता है, संवैधानिक मूल्यों (समानता, न्याय, शिक्षा, पंचायती राज) की वास्तविकता पर प्रश्न उठाता है तथा स्वतंत्र भारत में जारी सामाजिक शोषण को उजागर करता है।

हाशिए के घुमंतू समाज को मुख्यधारा में लाने की वैचारिक प्रतिबद्धता :–

'नटनी' का सबसे मजबूत वैचारिक आधार हाशिए के नट समाज को साहित्य की मुख्य पृष्ठभूमि पर स्थापित करना है। उपन्यासकार ने इस समुदाय की संस्कृति, रीति–रिवाज, भाषा, सामुदायिक एकता और दैनिक संघर्ष को जीवंत रूप से चित्रित किया है। यह प्रयास दलित–आदिवासी–घुमंतू साहित्य की निरंतरता

को मजबूत करता है। स्वतंत्र भारत में भी घुमंतू जातियाँ (नट, बाजीगर, सपेरा आदि) सरकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हैं। उपन्यास यह सवाल उठाता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के बावजूद ये समुदाय क्यों 'अदृश्य' बने हुए हैं? रज्जो का चरित्र इस 'अदृश्यता' को तोड़ता है–**"वह शिक्षा ग्रहण करती है, सामंती शोषण के विरुद्ध खड़ी होती है और पंचायत चुनाव जीतकर सत्ता में प्रवेश करती है।"**[1] यह वैचारिक दृष्टि आज प्रासंगिक है क्योंकि घुमंतू जीवन आधुनिक विकास मॉडल (शहरीकरण, भूमि अधिग्रहण) से सबसे अधिक प्रभावित है। उपन्यास नट समाज की सांस्कृतिक धरोहर को केवल पीड़ा के रूप में नहीं, बल्कि सकारात्मक पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे साहित्य में 'अन्य' की आवाज को स्थान मिलता है, जो मुख्यधारा के साहित्य को चुनौती देता है।

सामंतवाद, जातीय अहंकार और पंचायती राज की प्रासंगिकता :–

उपन्यास में जिगर सिंह सामंतवाद का प्रतीक है–वह नट समुदाय का शोषण करता है, उनकी मेहनत हड़पता है और उन्हें दास की तरह रखता है। रज्जो शिक्षा को हथियार बनाती है–**"हवेली से दो महिलाएं चली थीं, बीसियों का कारवां बन गया। महिलाओं ने पर्चे हाथ में ले लिए और उनको हवा में फहराती, आगे बढ़ती नारे लगाने लगी थीं–'जीतेगी भई जीतेगी' रीतासिंह जीतेगी"**[2] यह पंचायती राज व्यवस्था की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। **"रज्जो हथेली माथे पर फेरती हुई बोली–''माँ जी अगर मैं जीती पहल उसी नेकी से होगी।'' 'बहू' जीती समझ। रज्जो खुद में खोयी रही, 'मीना हवेली के उत्पीड़न, हथकण्डे, दोगलापन, दाग–दगा, लत–घूँस, लाभ– लोभ, दुराचार, अफसरों से मिलीभगत और गाँव की लाचारी से जर्रा जर्रा परिचित है। हवेली की आँतों में अमीबा की भाँति भ्रष्टाचार घुसा है।"**[3] उपन्यासकार यह संदेश देता है कि सच्ची आजादी केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक भी होनी चाहिए।

स्त्री–चेतना, लिंग–समता और जुझारू नारी चरित्र :–

रज्जो उपन्यास की केंद्रीय नायिका है, जो नट समाज की स्त्री की दासता, शोषण और संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है। नट समाज में स्त्री नाच–गान से परिवार चलाती है, लेकिन पुरुष प्रधान व्यवस्था में उसकी आवाज दबाई जाती है। रीतासिंह का जुझारू चरित्र–'**रीतासिंह ने रस्सी की चार तह की और सर्कस के खिलाड़ी की भाँति घुमाती, उस ओर बढ़ती गयी, जहां बेतहाशा शोर उठा था।**'[4] उपन्यास स्त्री को केवल पीड़ित नहीं दिखाता, बल्कि परिवर्तन की वाहक बनाता है। शीतलदेवी जैसे पात्र करुणा और मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वैचारिक दृष्टि आज प्रासंगिक है क्योंकि ग्रामीण और हाशिए के समाजों में स्त्री शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रज्जो का चरित्र हर स्त्री को दृढ़ निश्चयी होने का संदेश देता है–वह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी परिवर्तन लाती है।

रज्जो की पृष्ठभूमि और सामाजिक संदर्भ :–

रज्जो खानाबदोश नट जाति से संबंधित है–एक ऐसा समुदाय जो सदियों से बिना स्थायी घर, जमीन या सामाजिक मान्यता के खुले आसमान तले जीवन जीता आया है। नट समाज की महिलाएँ मुख्य रूप से नाच–गान, लोक– कला और प्रदर्शन के माध्यम से परिवार की आजीविका चलाती हैं, लेकिन मुख्यधारा का समाज उन्हें 'नीच' और 'अछूत' मानकर तिरस्कृत करता रहा है। रज्जो इसी व्यवस्था में जन्मी और पली–बढ़ी है, जहाँ स्त्री की भूमिका सीमित और शोषणपूर्ण रही है। उपन्यास की शुरुआत में वह एक सामान्य नटनी के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंतरिक चेतना और जागृति धीरे–धीरे उसे एक विद्रोही और क्रांतिकारी व्यक्तित्व में बदल देती है।

स्वतंत्र भारत में जारी शोषण और सामाजिक न्याय का प्रश्न :–

उपन्यास स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ से शुरू होता है (भारत छोड़ो आंदोलन, गांधीजी के नारे, क्रांतिकारियों का जोश), लेकिन स्वतंत्र भारत में भी शोषण जारी रहने का चित्रण करता है। **"सामंती ढाँचे, मुखबिर संस्कृति और जातीय शोषण आजादी के बाद भी बने रहे। रज्जो का संघर्ष यह दिखाता है कि राजनीतिक आजादी के बावजूद सामाजिक न्याय अधूरा है।"**[5] यह वैचारिक प्रासंगिकता संवैधानिक मूल्यों की विफलता पर सवाल उठाती है। घुमंतू जातियाँ आज भी भूमि, शिक्षा और पहचान से वंचित हैं। उपन्यास यह संदेश देता है कि सच्चा परिवर्तन शिक्षा, संगठन और प्रतिरोध से ही संभव है।

स्त्री–अस्मिता और पितृसत्तात्मक नियंत्रण :–

'नटनी' की केंद्रीय समस्या स्त्री–अस्मिता का संकट है। नायिका की पहचान उसकी कला से निर्मित होती है, किंतु समाज उसे स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करता। उसकी देह, उसकी गति, उसका नृत्य–सब कुछ पुरुष–दृष्टि के अधीन कर दिया जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्री कलाकार की स्वतंत्रता सीमित है। मंच पर वह आकर्षण का केंद्र होती है, किंतु मंच से उतरते ही वह तिरस्कार और अवहेलना की पात्र बन जाती है। यह विरोधाभास स्त्री की सामाजिक स्थिति की गहरी विडम्बना को उजागर करता है। समकालीन स्त्रीवादी विमर्श में देह – राजनीति का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'नटनी' इस विमर्श से सीधा संवाद करती है। नायिका की देह केवल उसकी पहचान नहीं, बल्कि सत्ता का उपकरण बन जाती है। पुरुष समाज उसकी देह के माध्यम से अपनी वर्चस्ववादी मानसिकता को पुष्ट करता है।

कला, बाजार और सांस्कृतिक शोषण :–

समकालीन समाज में कला का बाजारीकरण एक प्रमुख यथार्थ है। 'नटनी' इस प्रक्रिया की तीखी आलोचना प्रस्तुत करती है। कला, जो कभी आत्म–अभिव्यक्ति और सामाजिक चेतना का माध्यम थी, अब मनोरंजन उद्योग का हिस्सा बन चुकी है। नायिका की कला उसकी आत्मा की आवाज न रहकर दर्शकों की मांग और आयोजकों के लाभ का साधन बन जाती है। यह स्थिति आज के फिल्म उद्योग, रियलिटी शो और सांस्कृतिक उत्सवों से गहरा साम्य रखती है। कलाकार की प्रतिभा का उपयोग तो किया जाता है, किंतु उसकी सामाजिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा उपेक्षित रह जाती है। यहाँ कथा केवल व्यक्तिगत शोषण की बात नहीं करती, बल्कि एक व्यापक सांस्कृतिक संकट की ओर संकेत करती है, जहाँ कला का मूल उद्देश्य विकृत हो गया है।

अम्बेडकरवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव :–

उपन्यास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध ध्येयवाक्य **"शिक्षा शेरनी का दूध है" को बार–बार चरितार्थ किया गया है। "रज्जो, जो पहले रस्सी पर चलकर करतब दिखाने वाली एक सामान्य नटनी थी, पढ़–लिखकर इस वाक्य को जीवन में उतारती है। शिक्षा उसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों (समानता, न्याय, शिक्षा का अधिकार) की समझ देती है, जिससे वह लोकतंत्र की शक्ति को पहचानती है।"**[6] अम्बेडकरवादी चेतना उपन्यास की मूल भावना है–शिक्षा को केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि शोषण से मुक्ति, जातीय दासता से छुटकारा और सामाजिक–राजनीतिक सशक्तिकरण का माध्यम माना गया है। लेखक ने रज्जो के माध्यम से दिखाया है कि जब हाशिए का व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह अंधेर नगरी चौपट राजा वाली व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। रज्जो शिक्षा के बल पर पंचायती राज चुनाव लड़ती है, सरपंच बनती है और सदियों से शोषण का प्रतीक रही हवेली (सामंती राजतंत्र) को ध्वस्त करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाती है।

निष्कर्ष :–

'नटनी' उपन्यास की वैचारिक प्रासंगिकता बहुआयामी और गहन है। यह हाशिए के घुमंतू समाज

को मुख्यधारा में लाने, सामंतवाद–जातिवाद का विरोध, स्त्री–सशक्तिकरण, शिक्षा की भूमिका, पंचायती राज की वास्तविकता और स्वतंत्र भारत में जारी शोषण जैसे मुद्दों को उठाता है। रत्नकुमार सांभरिया की लेखनी जनवादी, प्रतिरोधी और संवेदनशील है–यह साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाती है। उपन्यास न केवल नट समाज की आवाज बनता है, बल्कि समकालीन भारत के सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। यह कृति हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो पाठकों को विचार करने और बदलाव के लिए प्रेरित करती है।

– डॉ. सुनील कुमार
हिन्दी विभाग,
गुरुकुल काँगड़ी (समविश्वविद्यालय)
हरिद्वार– 249404, (उत्तराखंड)
मो. 9050072171 WhatsApp - 9050072171

संदर्भ :

1. सांभरिया रत्नकुमार, 2025, नटनी, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 156
2. सांभरिया रत्नकुमार, 2025, नटनी, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 192
3. सांभरिया रत्नकुमार, 2025, नटनी, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 139
4. सांभरिया रत्नकुमार, 2025, नटनी, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 186
5. सांभरिया रत्नकुमार, 2025, नटनी, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 231
6. सांभरिया रत्नकुमार, 2025, नटनी, प्रथम संस्करण, सेतु प्रकाशन, नोएडा, पृष्ठ 2025

Resisting Caste-based Discrimination through Dharma in Baburao Bagul's Bhohada

- Niraj Raj[1]
Research Scholar
- Dr. Pramod Kumar[2]
Professor

Abstract :

The paper examines how Baburao Bagul's short story Bohada critiques Dalit discrimination by using dharma for their upward mobility. By portraying characters trapped in the complex web of caste hierarchies, Bagul depicts the ways in which Dharma is often manipulated to sustain oppression on Dalits. The story of Bohada becomes an example of resistance, where Dalits challenge and reinterpret the religious beliefs that bind them. Through an analysis, this paper explores how Baburao Bagul redefine Dharma as a force of assertion rather than a tool of subjugation thus offering a way to resist caste-based discrimination in society.

Keywords : Baburao Bagul, Dalit, Dharma, Marginalised, Resistance

Introduction :

Baburao Bagul's poignant short story Bohada reflects the dark reality of

caste-based discrimination faced by Dalits in India. It is a most prominent work in Marathi Dalit Literature which depicts the struggle and defiance of Dalit community against this dominant structure. The narrative revolves around the central theme of Dharma which is conventionally known as a moral duty that govern one's conduct. Bagul through his work Bohada, critiques the manipulation of Dharma by the upper caste to channelize caste-based discrimination in the contemporary India, whereas also offering a different perspective of Dharma as a tool of assertion for the Dalits. Bagul tries to redefine Dharma to resist cast discrimination by enabling his character to challenge the religious beliefs imposed on them.

Dharma : A tool for subjugation, Subversion and Solidarity

Conventionally in the Hindu social structure, Dharma is often associated to the vile caste system which determine different roles and duties to person based on their inheritance in the society (Ambedkar 59). In conformity with this, an individual's caste decide their Dharma and turning away from it could result in punishment and being pushed away to the periphery of the society. The upper caste uses Dharma as tool to relegate Dalits and to enjoy the privileges of being top of the barrel, “There is no shastrik basis for such a sin” (Bagul 21). Bagul skilfully showcased the conventional interpretation of Dharma being flawed as it gives religious rightfulness to caste-based discrimination.

The story revolves around a Dalit character named Damu, asking to perform as Narasimha in village's Bohada festival. Initially the upper caste denied him stating, “Ay kabhi hoga nahin, main aisa satyaanaash honeku doonga nahin” (23), but due to the warning from village administration against caste-based discrimination, they devise a strategy and ask him to pay if he wish to perform "it will cost two hundred rupees" (25). This is symbolic of power and authority as in contrast to Damu's socio-economic condition which is reflective of his indelible position in caste hierarchy. Damu's role in Bohada becomes a metaphor for how Dharma is used to impose social duty on Dalits and pushing them in the nexus of poverty and inequality. However he adopt the role of Narasimha in Bohada but his caste ensure that he could never get out from this societal oppression. Bagul through his narrative interrogate the legality of a

system where moral duty is decided by birth in lieu of person's action. He indicate the concept of misinterpreted dharma is fundamentally corrupt as it does not allow basic human dignity to the Dalit people.

Bagul in his story Bohoda, highlights the necessity of collective resistance and solidarity in rebelling against caste-based discrimination. The celebration is itself is a communal occasion that brings different members of the Dalit community together to take part in the shared cultural and religious tradition. While the celebration is rooted in the society to symbolize unity but upper-caste communities did not allow any Dalit boys to participate, it is used as a tool by them to discriminate against the Dalits and have control over the religious and social practices. As Bagul states, "This kind of thing, these out-of-the-way religious practices, will never happen here" (20). However, Damu along with other Dalit community members demanded to have a song, a Narsimha song. The song has a religious relevance in the society as it was a big honor to perform it. Their solidarity for the celebration asserts their cultural identity and resists to erase the discriminated religious beliefs of the upper-caste. Damu's performance symbolizes the collective resistance against the imposed social norms and caste hierarchy as it brought the consciousness within Dalit community as Bagul writes, “Next year, we will dance as the five Pandavas. And then let them bring down death or destruction, it will be all the same to us” (32).

Conclusion

Baburao Bagul in his story Bohada, delivers a mocking indictment of the caste system and its manipulative use of Dharma to legitimize caste-based inequality. Bagul exposes the higher castes' dishonesty and immorality by subverting traditional conceptions of Dharma. They exploit religious and social standards to retain their supremacy. At the same time, Bagul reimagines Dharma as a means of resistance for the oppressed, empowering the Dalit community in the novel to defy the caste system and claim their autonomy. The Bohada festival represents both Dalit oppression and resistance, highlighting the caste system's paradoxes while also providing a platform for social solidarity and creative expression. Bagul's reinterpreting of Dharma as a weapon for

the justice and equality offers an influential vision of resistance against caste-based discrimination and making Bohada a significant work in the Dalit literary canon.

- Niraj Raj[1]
Research Scholar
Sharda School of Humanities
and Social Sciences Sharda University
Mobile : 9576648375

- Dr. Pramod Kumar[2]
Professor
Sharda School of Humanities
and Social Sciences, Sharda University
Contact number: 9818044504

References :

Ambedkar, Bhimrao Ramji. Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches. 1979.

Bagul, Baburao. When I Hid My Caste. Translated by Jerry Pinto, Speaking Tiger Publishing Pvt. Ltd; c2018.

Olivelle, Patrick. "IX. Caste and Purity: A Study in the Language of the Dharma Literature." Language, texts, and society: explorations in ancient Indian culture and religion.-(Kykéion. Sez. 1.: Scienze delle religioni; 4) (2005): 1000-1029.

Radhakrishnan, Sarvepalli. "The Hindu Dharma." The International Journal of Ethics 33.1 (1922): 1-22.

Shyma, P. "Baburao Bagul, When I Hid My Caste." Asiatic: IIUM Journal of English Language and Literature 15.2 (2021) : 159-162.

The strategic Role of State Bank of India (SBI) in Financing Farmer Producer Organizations (FPOs)

- Dr. Abhishikha Parmar

Abstract :

Farmer producer organizations (FPOs) have emerged as the primary vehicle for aggregating small and marginal farmers in India to achieve economites of scale. However, the "missing middle" in agriculture credit remains a hurdle. This paper examines the role of the State Bank of India (SBI) in bridging this gap through specialized credit products, its alignment with the central sector scheme far 10,000 FPOs and the impact of its financing on FPO sustainability.

Introduction :

With over 85% of Indian farmers categorized as small or marginal (holding < 2 hectares), individual bargaining power is negligible. FPO act as collectives to a improve access to inputs and markets. As India's largest public sector bank, SBI plays a pivotal role in priority sector lending (PSL), transitioning from individual crop loans

(KCC) to institutional financing for FPOs.

SBI's Specialized Financing Framework.

SBI Provides a multi-layered financial suite tailored to the lifestyle of an FPO-from gestation to maturity.

Future	Details
Facility Types	Cash Credit (CC), Term Loans (TL) Bank Guarantee (BG), and letter of credit (LC)
Loan Quantum	Minimum Rs. 1 Lakh, Maximum up to Rs. 100 crores (for large-scale federation)
Interest Rates	Competitive rates typically linked to EBLR (External Benchmark Lending Rate.)
Repayment	Term loans up to 10 years (including a 24 months moratorium.
Margin	10% to 20% depending on the project cast and credit guarantee coverage.

Key Schemes and Credit Support :

- SBI integrates its internal products with Government of India (GOI) and NABARD initiatives :

- Agri infrastructure Fund (AIF) :- SBI provides term loans for post harvest management infrastructure (warehouses, cold chains) with a 3% interest subvention.

- Credit Guarantee Coverage :- To solve the "collateral" problem, SBI utilizes the NAB Sanrakshan and CGTMSE Schemes, offring collateral - free loans up to Rs. 2 crores.

PM-FME Scheme :- SBI finances FPOs involved in micro - food processing, providing seed capital and credit - linked Subsidies.

Challenges in SBI-FPO Linkage

Despite the robust framwork, several research findings highlight systemic bottenecks.

1. Low equity base : Many FPO struggle to meet SBI's minimum equity requirement for larger loans.

2. Lack of collateral :- For loans exceeding the credit guarantee limit (e.g., > Rs. cr.), FPOs often lack the fixed assets required by the bank.

3. Governance Issues :- Banks frequently cite poor bookkeeping and a lack of professional management within FPO as high-risk factors.

4. Digital Gap :- While SBI has moved toward digital lending, many rural FPOs struggle with the documentation and digital literacy required for "YONO Krishi" or online applications.

Impact Analysis

Research indicates that FPOs financed by SBI Show :

1. Financial Inclusian : Successful SBI linkage offten acts as a "green signal" for other private investors and buyers.

2. Reduced cast of cultivation : Due to bulk procuremnet of inputs financed via cash credit

3. Improved price realization : Term loans for processing unit allow FPOs moves up the value chain.

Conclusion and Policy Recommendations

SBI is no longer just a lender but an ecosystem enabler for FPOs. To enhance this role, the bank should consider "performance based lending rather than purely asset - bassed lending Further-more, integrating Blockchain for supply chain transparency could reduce the perceived risk for the bank, leading to lower interest rates for the farmers.

- Dr. Abhishikha Parmar
Mob. 83196 34382

References :

SBI Annual report 2023-24 : Rural and Agricultural Banking Division.

Government of India (2025) operational Guidelines for 10,000 FPO Scheme.

NTBM (2025) Determinants of Financial performance of FPOs.

'ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं'

– सुरेन्द्र (शोधार्थी)

हाल ही में 'ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं' ठेठ हरियाणवी संस्कृति का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक शहर के डैहरी मोहल्ले के एक दलित समुदाय (चमार) में जन्मे तथा वर्तमान समय में प्रतिष्ठित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (A++) के इतिहास विभाग में कार्यरत प्रोफसर एवं पूर्व अध्यक्ष और डीन रहे डॉ. सरवर कुमार चहल द्वारा लिखित 19 अध्यायों में विभाजित 261 पृष्ठीय आत्मकथा का प्रथम प्रकाशन फरवरी 2025 ई. में हिन्द युग्म (नोएडा) से हुआ। हरियाणा जैसे राज्य में दलितों में साहित्यिक चेतना का सर्वथा अभाव रहा है–इसी कारण यहाँ दलितों द्वारा आत्मवृत्त लिखने की प्रवृत्ति सामान्यतः देखने को नहीं मिलती। यह प्रदेश तो वैसे भी युद्धों की भूमि रहा है। प्राचीन महाभारत युद्ध के अतिरिक्त छः ऐतिहासिक लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी जा चुकी हैं जैसे तराइन के तीन युद्ध (सन् 1191, 1192 व 1216 ई.) व पानीपत के तीन प्रमुख युद्ध (सन् 1526, 1556 व 1761 ई.) आदि। यहाँ के युवाओं में खेल के क्षेत्र जैसे कबड्डी, कुश्ती व भारत्तोलन में कैरियर बनाने को लेकर अधिक उत्साह देखने को मिलता है। 23 दिसम्बर, 2016 को रिलीज हुई सुपरहिट हिंदी फिल्म 'दंगल' भी यहीं की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

बाबा साहब की चेतना के परिणामस्वरूप दलित आत्मकथाएँ सर्वप्रथम सत्तर के दशक में मराठी भाषा में तत्पश्चात् नब्बे के दशक में हिंदी में लिखी गई। हाल के वर्षों में हरियाणा में भी दो दलित आत्मकथाएँ लिखी गई–प्रथम कैथल जिले के राजौंद गाँव की रहने वाली डॉ. कौसल्या उर्फ कौशल पंवार जो वाल्मीकि समुदाय से प्रोफेसर बनने वाली पहली दलित महिला है और वर्तमान समय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत है उनके द्वारा लिखित 'बवंडरों के बीच' (1 जनवरी, 2021) तथा दूसरी 'जख्म अभी ताजा हैं'।

आत्मकथा मूल रूप से डॉ. सरवर कुमार चहल ने 'भारतीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान' (पूर्व राष्ट्रपति भवन) शिमला में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट 'महात्मा ज्योतिराव फूले' पर शोधकार्य के दौरान सन् 2019 व जून 2020 ई. में देशव्यापी लॉक डॉउन के दौरान लिखी। लिखने का विचार तो लेखक के मन में कॉलेज के दिनों से ही उत्पन्न हो गया था, इसलिए वे उस दौरान नियमित रूप से (1985–86) डायरी लेखन करते रहे। डायरियों के पन्नों में लिखे आत्मवृत्त या कहे संस्मरणों को लेखक ने आत्मकथा का रूप देने का प्रयास तो कई बार किया लेकिन यह सोचकर इसे अधूरा छोड़ दिया कि जब वह जीवन में बड़े आदमी बन जाएँगे अथवा एक मुकाम हासिल कर लेंगे तभी लिखेंगे। अब चूँकि लेखक एक प्रोफेसर जैसे सम्मानित पद पर कार्यरत है तब इसका लिखा जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। यह ऐसे समय में लिखी गई है जब दलित आत्मकथाओं का लिखा जाना पिछले कुछ वर्षों से लगभग बंद सा ही हो गया है।

रोहतक हरियाणा का गढ़ रहा है। इस शहर की कुछ विशेषताएँ हैं जैसे लठमार भाषा, अक्खड़ता, एक खास तरह का 'डिठोरा' या अकड़, थोड़ी उजड्डता, गँवारुपन, आक्रामकता, स्वाभिमान, अति–आत्मविश्वास, बहादुरी व हास्य बोध आदि। इसलिए इस आत्मवृतांत में हरियाणवी संस्कृति, जीवन–दर्शन, मूल्यों व मुहावरों की भी झलक देखने को मिलती है।

सरवर जी का जन्म रोहतक शहर के डैहरी मोहल्ले में 6 सितंबर, 1968 ई. को हुआ जो इनके पिताजी द्वारा घरेलू बहीं में दर्ज कराई गई जन्म–तिथि है। डैहरी मोहल्ला रोहतक के कुछ गिने चुने पुराने मोहल्लों में से एक है जो शहर की उत्तरी दिशा में बिल्कुल बाहरी क्षेत्र में पड़ता है। इस दिशा में तीन मोहल्ले हैं–पहाड़ा, सिलारा व डैहरी। पहाड़ा में अधिकांशतः संख्या में वाल्मीकि रहते थे जो सूअर पालने व साफ–सफाई का काम करते थे। सिलारा में कुम्हार

रहते थे जो गधे एवं खच्चर के अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन बनाते थे और डैहरी में मुख्यतः चमार एवं धानुक रहते थे। चमारों की पुरानी बस्ती जिसे बगड़ कहा जाता था, सड़क के उस पार दक्षिण की तरफ थी जबकि नई बस्ती सड़क के इस पार उत्तर दिशा में खोकराकोट के नजदीक थी। दरअसल मनुवादी व्यवस्था के आधार पर अमूमनः दलितों के घर बस्ती बगड़ या कहे टोला दक्षिण दिशा में ही होते है। इन्हें इस दिशा में बसाए जाने का एकमात्र कारण गाँव का मल–मूत्र व बरसात का सारा पानी इन्हीं की बस्ती से होकर गुजरने के अतिरिक्त इस दिशा को अशुभ मानने से भी है।

आत्मकथा में आए एक प्रसंग के अनुसार सरवर जी एक बार चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। साथ में बैठे एक ब्राह्मण सह–यात्री से परस्पर संवाद हो रहा था कि अचानक ब्राह्मण द्वारा उनकी जाति पूछे जाने पर और यह पता चलते ही कि यह व्यक्ति भंगी जाति से ताल्लुख रखता है–ब्राह्मण यात्री का बातचीत करने का तरीका और रवैया एकदम से बदल जाता है। ठीक यही स्थिति ओमप्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित आत्मकथा 'जूठन' (1997) में भी देखने को मिलती है– जब वे पत्नी चंदा के साथ ट्रेन में जयपुर से दिल्ली का सफर कर रहे थे।

सन् 1973 ई. में सरवर जी का दाखिला घर के समीप स्थित कायस्थान प्राइमरी स्कूल में हुआ। उस समय इनकी आयु मात्र चार या साढ़े चार साल रही होगी। अध्यापिकाओं को बहन जी कहने का रिवाज आम था। उस जमाने में पाँचवीं कक्षा बोर्ड की हुआ करती थी। रोहतक शहर के स्कूलों में अधिकतर अध्यापक और अध्यापिकाएँ पंजाबी समुदाय से थी। इसका मुख्य कारण विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को इस शहर में मुसलमानों द्वारा खाली छोड़ी गई जमीन पर बसाया जाना था। इसी कारण यहाँ की संस्कृति पर पंजाबियत का असर भी देखने को मिलता है।

स्कूल के दिनों में अबोध बालक सरवर का एक मनुवादी मानसिकता वाले शिक्षक भगत राम से पाला पड़ा। शिक्षक ने इन्हें पीटते हुए जातिवादी शब्द कहे। एक बानगी देखिए, "साला हरामी चमार–गिंढल ! बहुत होशियार बनता है ! आज फँस गया न !" (ज़ख़्म अभी ताजा हैं–पृ.58) दरअसल हरियाणा व दिल्ली देहात के गाँवों में चमारों को अपमानजनक ढंग से गिंढल कहा जाता था। चमारों को लेकर एक जातिवादी कहावत भी मशहूर है, "गिंढल जात चमाराँ की, जुत्ती गाँड्डे याराँ की ।" (ज़ख़्मअभी ताजा हैं–पृ. 58) लेखक के माँ व पिताजी ने तमाम तरह के अभावों, कष्टों व संघर्षों से जूझते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया–लिखाया व इस काबिल बनाया कि वे भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके। अभावों के दिनों में माँ का यह कहना कि, "नहीं–नहीं ! बच्चों को हम पढ़ने से नहीं हटाएँगे। क्या पता कल को हमारा कौन सा बच्चा पढ़–लिखकर कितना बड़ा साहब बन जाए।" (ज़ख़्म अभी ताजा हैं– पृ. 83) हुआ भी यही लेखक के बड़े भाई रोहतास– ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मैनेजर के पद पर, छोटा भाई सूरज–सरकारी स्कूल में जूनियर लेक्चरर और स्वयं लेखक एम.ए,एम.फिल, पीएच.डी. व नेट–जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करके कुरुक्षेत्र जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बने ।

आर्थिक अभावों से जूझने और पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने की उम्मीद में सरवर जी ने बाल मजदूर का सफर तय करते हुए मैट्रिक व इंटर की परीक्षा देते ही छुट्टियों के समय में लिफाफे बनाकर बेचना, आइसक्रीम बेचना, सूखे मेवों की दुकान पर काम करना, कभी कैम्पा कोला की फैक्टरी में हेल्पर का काम करने के अतिरिक्त चाय की दुकान पर भी काम किया। एम.ए. इतिहास की पढ़ाई के दौरान लेखक पर मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक प्रोफेसर एस.पी. शुक्ला का गहरा प्रभाव पड़ा । इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने एम.फिल् पीएच.डी, के शोध प्रबंध लिखे। 20 दिसम्बर, 1991 ई. को इनका महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक में पीएच.डी. में पंजीकरण हुआ ।

एक बार इन्होंने अपने शोध–निर्देशक को किसी कार्य में व्यस्त पाकर उनसे नमस्ते नहीं की और चुपचाप

उनके कार्यालय में जाकर बैठ गए–परिणामस्वरूप अगले दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसकी एक बानगी देखिए, "ठीक–ठाक रहो वरना में तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकलवा दूँगा । यह तो तुम 'हरिजन' हो इसलिए...।" (ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं–पृ.160) इसके अलावा इनके शोध–निर्देशक का इनका अन्य प्रोफेसरों से परिचय करवाने का तरीका, "बड़ा इंटेलीजेंट लड़का है और 'हरिजन' है।" (ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं–पृ.162) मानो एक दलित को हरिजन से ऊपर उठने का अधिकार है ही–नहीं ।

बाबा साहब को पढ़ने के पश्चात् सरवर जी ने भी पीएच.डी. शोध–कार्य के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर पर 'बायोग्राफिकल स्टडी' करने की अपनी इच्छा जाहिर की। ऐसा सुनते ही प्रो. शुक्ला जी ने कहा कि, "अंबेडकर पर बहुत काम हो चुका है ।"(ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं–पृ.161) स्ट्रगल ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस (1885–1947) विषय भी उन्हें नागवार गुजरा। लगभग यहीं स्थिति डॉ. दयाराम जाटव द्वारा लिखित आत्मकथा, 'मेरा सफर, मेरी मंजिल' (2000) में भी देखने को मिलती है। अक्तूबर, 1960 ई. में आगरा विश्वविद्यालय की दर्शन शास्त्र शोध समिति के सामने जब, 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर का समाज–दर्शन' नामक शोध विषय स्थायी पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया तब सभी सदस्यों ने उसका घोर विरोध किया। दो सदस्यों ने तो उक्त विषय को पूर्णतः खारिज करते हुए कहा था कि डॉ. अंबेडकर का कोई समाज–दर्शन नहीं था। वह तो मात्र एक 'समाज सुधारक' थे। डॉ. तिवारी शोध समिति के संयोजक थे उन्होंने विषय की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए सभी सदस्यों को विश्वास में लिया और कहा कि, "विषय की स्वीकृति से कोई हानि नहीं है। यदि डॉ. अंबेडकर का कोई समाज–दर्शन है तो यह शोधार्थी ही खोज कर सकेगा।" (मेरा सफर, मेरी मंजिल–पृ.29)इस तरह प्रस्तुत शोध विषय'डॉ. बी. आर. अंबेडकर का समाज– दर्शन' को संशोधित करके "डॉ. बी.आर.अंबेडकर के समाज–दर्शन का एक आलोचनात्मक आंकलन"(मेरा सफर, मेरी मंजिल–पृ. 29) शीर्षक से पंजीकरण की स्वीकृति मिली ।

आखिरकार शुक्ला जी ने भी सरवर के साथ यही किया। इनका जो विषय अप्रूव किया वह था–इंडियन नेशनल काँग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस (1921–1947)। गांधीवादी युग से जुड़ा यह विषय देकर शुक्ला जी इन्हें गांधी को गहराई से पढ़ने हेतु बाध्य कर रहे थे। आज वर्तमान समय में भी भारत के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में ऐसा ही देखने को मिलता है। दलित छात्र या छात्रा यदि दलित अध्ययन करना चाहे भी तो उन्हें नहीं करने दिया जाता। उनके शोध विषयों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या जानबूझकर उनमें संशोधन। आत्मकथा में सरवर जी ने 90 के दशक में देश में मंडल कमीशन आने के बाद हरियाणा में दलित जातियों पर हुए हमले की घटनाओं का भी जिक्र किया है । यह कमीशन आया तो उपेक्षित जतियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए था लेकिन अज्ञानतावश हरियाणा के जाट लोग खुले–आम आग उगल रहे थे उनका यह कहना कि, "चमार–चूहड़े सब कुछ खा गए! साथ ही वे जगह–जगह दलितों की बस्तियों पर भी हमले कर रहे थे। देश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएँ एकाएक बढ़ गई थीं और मेहराना, चंडूर तथा कुम्हेर आदि गाँवों से उनके क्रूरतापूर्वक नरसंहार के मामले सामने आ रहे थे ।" (ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं–पृ. 139) जबकि मंडल रिपोर्ट का दलित वर्गों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस आंदोलन का सर्वाधिक निशाना इन्हें ही बनाया गया।

लगभग पौने दो साल रेवाड़ी के एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडहॉक की नौकरी (19 सितंबर, 1992–12 मई, 1994) करने के पश्चात् सरवर जी का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में लेक्चरर पद हेतु साक्षात्कार 8 जून, 1995 को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हुआ। साक्षात्कार लेने वाले पाँच व्यक्ति थे जिनमें कु.वि. के उप–कुलपति, विभागाध्यक्ष व जेएनयू में कार्यरत आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्रा व दो अन्य व्यक्ति पंजाब विश्वविद्यालय से थे। कुलपति व विभागाध्यक्ष

महोदय अपने उम्मीदवार के चयन को लेकर पहले से ही आश्वस्त बैठे हुए थे। चूँकि चहल जी का साक्षात्कार एक घंटे से भी अधिक समय तक चला व प्रो. विपिन चंद्रा ने इनमें भविष्य की अपार संभावनाए देखते हुए इनके चयन को अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान की। कुलपति व विभागाध्यक्ष महोदय अपने उम्मीदवार का चयन न हो पाने के कारण मन–मसोस कर रह गए। जब उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा तो उन्होंने इनसे बदला लेने के लिए लगभग पाँच महीने तक (5 नवम्बर, 1995 तक) इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया ।

विभाग में आने के कुछ समय बाद ही सरवर जी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित डॉ. अंबेडकर केंद्र का 'डिप्टी डायरेक्टर' नियुक्त कर दिया गया। कुछेक शिक्षकों को छोड़कर सभी इनकी विचारधारा के सख्त खिलाफ थे । जब इन्होंने अपने शोध छात्रों को दलित अध्ययन संबंधी टॉपिक दिए तो उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया गया। 25 मई, 1999 ई. को इन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की और से एक गोपनीय पत्र मिला–जिसमें विभागीय शिक्षकों ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी । मनगढ़ंत आरोप लगाकर इन्हें परेशान किया जाने लगा लेकिन सरवर जी भी परिस्थितियों से हार मानने वाले इंसान नहीं थे इन्होंने तो बचपन से ही विपरीत हालातों का सामना किया था। ये डरे नहीं बल्कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत नई दिल्ली में एससी/एसटी अधिनियम 1989 के तहत उन पर कारवाई की। परिणामस्वरूप समझौता तो हो गया लेकिन आगामी समय में इनके प्रमोशनों में कई तरह के अड़ंगे लगाए गए ।

इन सब के बावजूद सरवर जी की मेहनत रंग लाई और इन्हें विश्वविद्यालय का 'यंगेस्ट प्रोफेसर' बनने का गौरव प्राप्त हुआ। सन् 2015 ई. में ये विभाग के चेयरमेन बने । सन् 2017 ई. में विश्वविद्यालय की NAAC टीम ने अपनी रिपोर्ट् में इतिहास विभाग को विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विभागों में से एक माना । विशेषकर NAAC टीम सरवर जी द्वारा स्थापित 'महात्मा फूले चेयर' की अकादमिक गतिविधियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी ।

समग्रतः कहा जा सकता है कि 'ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं' सिर्फ सरवर जी की आत्मकथा नहीं है बल्कि उन तमाम अभिशप्त जातियों की जीवन कथा हैं जो सदियों से शोषण और उपेक्षा का जीवन जीने के लिए विवश है। एक दलित व्यक्ति पढ़–लिखकर चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी या प्रोफेसर क्यों न बन जाए लेकिन परंपरागत मनुवादी व्यवस्था के तहत चले आ रहे समाज में उसकी हैसियत न के बराबर है। वह आज भी चूहड़ा या चमार ही कहलाने को बाध्य है। उसके ज़ख़्मों को बार–बार कुरेदा जाता है। इसी कारण लेखक ने इसका शीर्षक 'ज़ख़्म अभी ताज़ा हैं' रखा।

– **सुरेन्द्र**
पीएच.डी. शोधार्थी
हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
दूरभाष सं. 8920840861
पता : मकान नंबर. 15, मेन रोड
मदनपुर डबास, डाकघर–रानी खेड़ा, दिल्ली–81

शिकंजे का दर्द में चरित्र- विन्यास और दलित यथार्थ

– **डॉ. नीतामणि बरदलै**

प्रस्तावना : आत्मकथा साहित्य में चरित्र–चित्रण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आत्मकथा का कथानायक स्वयं लेखक होता है और उसके जीवन से जुड़े व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कथा के पात्र बनकर उभरते हैं। आत्मकथात्मक लेखन में पात्रों का चित्रण केवल व्यक्तिगत स्मृतियों का विवरण नहीं होता, बल्कि उस सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसमें लेखक का जीवन निर्मित होता है। इस दृष्टि से सुशीला टाकभौरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द में चरित्र–चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुशीला टाकभौरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द दलित साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें लेखिका ने अपने व्यक्तिगत जीवनानुभवों के माध्यम से दलित समाज के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक

यथार्थ को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। विशेषतः माता–पिता, नानी, पति तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से लेखिका ने दलित समाज की सामाजिक स्थितियों, संघर्षों और जीवन–यथार्थ को प्रकट किया है। इन पात्रों के माध्यम से न केवल लेखिका के जीवन–निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट होती है, बल्कि दलित समुदाय की सामाजिक पीड़ा, असमानता और संघर्ष का भी मार्मिक चित्र सामने आता है।

नानी : दलित स्त्री–शक्ति का प्रतीक : शिकंजे का दर्द में सुशीला टाकभौरे की नानी का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रूप में सामने आता है। नानी का जीवन अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण था, किंतु इन परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने आत्मसम्मान और साहस के साथ जीवन व्यतीत किया। वे एक स्वाभिमानी, परिश्रमी और कर्तव्यनिष्ठ महिला थीं, जो अपने पति के साथ मिलकर गाँव के कार्यों में सहयोग करती थीं। आर्थिक अभावों के कारण उन्हें जूठन, रोटी, अनाज और उतरन के कपड़ों से जीवन निर्वाह करना पड़ता था। बाद में जीविका के लिए उन्होंने नगर परिषद में भी कार्य करना प्रारम्भ किया।

नानी का व्यक्तित्व केवल श्रमशीलता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें गहरा आत्मसम्मान और सामाजिक चेतना भी विद्यमान थी। वे अपनी बेटी और नातिन – नातियों को भी स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती थीं। पति की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अत्यंत साहस के साथ परिवार की जिम्मेदारी निभाई और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। नानी के व्यक्तित्व में दलित चेतना और प्रगतिशील दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे जाति–आधारित भेदभाव और सामाजिक अन्याय के प्रति आक्रोश व्यक्त करती थीं और एक ऐसे समाज की कल्पना करती थीं जहाँ समानता और सम्मान का वातावरण हो। उनकी यह भावना दलित समाज के ऐतिहासिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा का प्रतीक है। नानी का स्वभाव अत्यंत ममतामयी था। माता–पिता के मजदूरी कार्य में व्यस्त रहने के कारण बच्चों की देखभाल का दायित्व प्रायः नानी ही निभाती थीं। वे बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहशील थीं और सुशीला को प्रेमपूर्वक 'सिलिया' कहकर पुकारती थीं। उनके व्यवहार में किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं था, जो उनके समानतावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही वे बच्चों को शिक्षा, परिश्रम और आत्मनिर्भरता का महत्व समझाती थीं। जातिगत अपमान और सामाजिक तिरस्कार को सहते हुए भी उन्होंने कभी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। तपती धूप में काम करना, प्यासे रहकर श्रम करना और समाज की अवमानना सहना उनके जीवन की कठोर वास्तविकताएँ थीं, किंतु उन्होंने इन्हें धैर्य और साहस के साथ स्वीकार किया। इस प्रकार नानी का चरित्र दलित स्त्री–चेतना, श्रम–संस्कृति और संघर्षशीलता का सशक्त प्रतीक बनकर उभरता है।

माँ : संवेदना, संघर्ष और स्त्री–अस्मिता की धुरी : सुशीला टाकभौरे के जीवन और व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माँ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। माँ का स्नेह, संवेदनशीलता और शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सुशीला के जीवन को दिशा प्रदान करता है। विशेष रूप से जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध उनका स्पष्ट विरोध सुशीला के भीतर सामाजिक न्याय और समानता की चेतना विकसित करता है।

माँ धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वे पूजा–पाठ में विश्वास रखती थीं, नवरात्रि के अवसर पर कन्या–भोजन कराती थीं और रामलीला देखने जाती थीं। किंतु धार्मिक आस्था के साथ–साथ उनमें सामाजिक जागरूकता भी थी। वे महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रभावित थीं और समाज में स्वच्छता तथा जागरूकता फैलाने का प्रयास करती थीं। माँ अत्यंत ममतामयी और कर्तव्यनिष्ठ महिला थीं। वे बच्चों की भावनाओं को भली–भाँति समझती थीं और अभावों के बावजूद उनकी छोटी–छोटी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती थीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। सामाजिक विरोध के

बावजूद उन्होंने सुशीला की पढ़ाई जारी रखी और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। माँ का व्यक्तित्व प्रगतिशील था। वे बेटों और बेटियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करती थीं और सभी बच्चों को समान अवसर देने का प्रयास करती थीं। वे अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनने और परिश्रम करने की शिक्षा देती थीं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे घर के कार्यों में दक्ष थीं। इस प्रकार सुशीला की माँ का चरित्र दलित स्त्री के संघर्ष, संवेदना और आत्मसम्मान की सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है।

पिता : श्रमशील और प्रगतिशील व्यक्तित्व : सुशीला टाकभौरे के पिता रामप्रसाद घांवरी एक मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। जातिगत भेदभाव – कारण उनकी शिक्षा केवल दूसरी कक्षा तक ही सीमित रह गई, किंतु वे शिक्षा के महत्व को भली–भाँति समझते थे। इसी कारण उन्होंने अपने बच्चों को प्रारंभ से ही पढ़ने–लिखने के लिए प्रेरित किया। पिता का व्यक्तित्व अत्यंत प्रगतिशील था। वे अंधविश्वास और रूढ़ परम्पराओं का विरोध करते थे तथा जाति–व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते थे। वे परिवार के लिए दिन–रात मेहनत करते थे और अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर बच्चों की जरूरतों को प्राथमिकता देते थे। पत्नी के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष था।

इस प्रकार सुशीला के पिता का चरित्र शोषित वर्ग के संघर्षशील, श्रमशील और प्रगतिशील प्रतिनिधि के रूप में सामने आता है।

सुंदरलाल टाकभौरे : द्वंद्वात्मक चरित्र : सुशीला टाकभौरे के पति सुंदरलाल टाकभौरे का चरित्र आत्मकथा में एक द्वंद्वात्मक रूप में प्रस्तुत हुआ है। वे पेशे से हाईस्कूल में कर्मचारी थे और स्वभाव से सरल, मृदुभाषी तथा साहित्य–प्रेमी व्यक्ति थे। उनकी आधुनिक सोच के कारण उन्होंने विवाह के बाद भी सुशीला को शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप सुशीला उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकीं।

किन्तु उनके व्यक्तित्व में पितृसत्तात्मक मानसिकता के कुछ अवशेष भी दिखाई देते हैं। पत्नी पर अधिकार–बोध के कारण वे कई बार कठोर व्यवहार भी करते थे, जिससे सुशीला को मानसिक पीड़ा का अनुभव होता था। इस प्रकार उनके चरित्र में प्रगतिशीलता और पारंपरिक पितृसत्ता दोनों का समन्वय दिखाई देता है।

निष्कर्ष : शिकंजे का दर्द में प्रस्तुत पात्र – संरचना केवल कथा के विकास का साधन नहीं है, बल्कि दलित समाज के यथार्थ का जीवंत दस्तावेज भी है। नानी, माँ, पिता और पति जैसे पात्रों के माध्यम से लेखिका ने दलित जीवन के संघर्ष, पीड़ा, अपमान और प्रतिरोध को अत्यंत मार्मिक और प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि दलित समाज का जीवन केवल पीड़ा का इतिहास नहीं है, बल्कि उसमें संघर्ष, आत्मसम्मान और परिवर्तन की आकांक्षा भी विद्यमान है। इस प्रकार शिकंजे का दर्द का चरित्र – विन्यास दलित साहित्य की उस परंपरा को सशक्त करता है जो समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों को आवाज देता है और सामाजिक समानता तथा मानव गरिमा के मूल्य को प्रतिष्ठित करता है।

– डॉ. नीतामणि बरदलै
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
डिगबोई महिला महाविद्यालय, डिगबोई
(डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, असम)
दूरभाष क्रमांक : 6913412180

सहायक ग्रंथ :

1. टाकभौरे, सुशीला. शिकंजे का दर्द. प्रथम संस्करण. दिल्ली : वाणी प्रकाशन, 2011.
2. कस्तवार, रेखा. स्त्री चिंतन की चुनौतियाँ. प्रथम संस्करण. दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2016.
3. चौधरी, विनोद. दलित चेतना और सुशीला टाकभौरे का साहित्य. प्रथम संस्करण. कानपुर : उत्कर्ष पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, 2020.
4. जैन, पुनीता. हिन्दी दलित आत्मकथाएँ : एक मूल्यांकन. प्रथम संस्करण. नई दिल्ली : सामयिक बुक्स प्रकाशन, 2017.

Climate Change, Agricultural Value Chains and Greenhouse Gas Emissions in the Vidarbha Region of Maharashtra : A Review of Impacts, Emission Sources and Pathways for Resilience

- Ravi N. Parmar[1]
- Dr. Vitthal Kauthale[2]

Abstract

Agricultural systems in the Vidarbha region of Maharashtra face an intensifying dual challenge: escalating climate variability that threatens food security and farmer livelihoods and substantial contributions to Greenhouse Gas (GHG) emissions that perpetuate global warming. This paper synthesises prevailing evidence on the climate change impacts across Vidarbha's agricultural value chains and examines the profile of GHG emissions from Indian agriculture with reference to the region's agro-climatic diversity and socio-economic vulnerability.

Drawing on long-term climatic data, national GHG inventories and an extensive review of peer-reviewed literature and policy documents, the study contextualises how rising temperatures, erratic monsoon patterns and intensifying drought frequency are adversely affecting smallholder farmers who constitute nearly 78 percent of the agricultural community in Vidarbha. Concurrently, emissions from enteric fermentation, rice cultivation, fertilizer-induced nitrous oxide and manure management collectively represent the dominant sources within India's agricultural GHG profile. The paper maps four critical research gaps namely absence of region-specific GHG data, lack of comparative tool analysis, inadequate climate risk mapping and no integrated adaptation-mitigation framework and articulates the research objectives that this study is designed to address. The findings are intended to inform evidence-based policy and practice for building sustainable and climate-resilient agricultural value chains in Vidarbha, consistent with India's Paris Agreement commitments.

Keywords : Climate change; Greenhouse Gas emissions; Vidarbha region; Agricultural value chains; Smallholder farmers; Climate resilience; GHG mitigation; Maharashtra; Agrifood systems; Climate-smart agriculture

1. Background

Climate change driven by the progressive accumulation of greenhouse gases (GHG) in the atmosphere, poses mounting threats to global ecosystems, economies and human livelihoods (IPCC, 2022). Agriculture foundational to human sustenance and national development is among the sectors most profoundly affected. Elevated global temperatures trigger increased frequency of extreme weather events, erratic precipitation patterns, prolonged droughts and flash floods all of which reduce crop yields, disrupt ecological equilibria and complicate pest and disease management (Yuan et al., 2023).

Beyond being a victim of climate change, agrifood systems are themselves significant contributors to the problem. GHG emissions from agriculture originate at the farm level through crop and livestock production; from land-use transformations such as deforestation and peatland drainage; and across pre- and post- production stages encompassing food manufacturing, transportation, retail, household consumption and food waste disposal (FAO, 2023). In 2021, global agrifood system emissions reached approximately 16 billion tonnes of carbon dioxide equivalent (Gt CO2eq), constituting around 30 percent of total anthropogenic GHG emissions (FAO, 2023).

India's agriculture sector provides livelihood support to about 42.3% of the population and contributes around 18.2% to GDP (Economic Survey 2023-24, Ministry of Finance). Agricultural losses attributable to extreme weather events are estimated at 0.25 percent of India's GDP annually (Singh et al., 2019). More acutely, climate stressors exacerbate smallholder debt burdens, with research establishing linkages between yield variability and farmer suicides in distressed regions (Carleton, 2017). The

agriculture sector accounted for 13 percent of India's total GHG emissions equivalent to 4,20,968 Gg CO2eq in 2019 (MoEF&CC, 2023).

2. Study Area, Scope and Methodology

The Vidarbha region encompasses 11 districts across two administrative divisions: the Amravati Division (comprising Buldhana, Akola, Washim, Amravati and Yavatmal) and the Nagpur Division (comprising Wardha, Nagpur, Bhandara, Gondia, Chandrapur, and Gadchiroli). Three distinct agro-ecological zones characterise the region: (i) Western Vidarbha, with annual rainfall between 700-950 mm; (ii) Central Vidarbha; and (iii) Eastern Vidarbha with rainfall exceeding 1,250 mm annually (Chapke, Dayakar, & Tonapi, 2017).

The study adopts a mixed-methods approach integrating: (i) an extensive review of peer-reviewed literature, policy documents and national GHG inventories; (ii) long-term analysis of temperature and precipitation data spanning 100 years across all 11 districts; (iii) comparative assessment of four IPCC-recognized GHG estimation tools and (iv) primary data collection from smallholder farmer communities across the study area. The 11 selected commodities reflect the region's economic and agronomic priorities, including cotton, soybean, paddy, pigeon pea, sorghum, wheat, and chickpea, alongside key livestock categories.

3 Impacts of Climate Change on the Vidarbha Region

Agricultural systems are increasingly susceptible to warming temperatures, associated aridity, altered precipitation regimes and the heightened frequency and duration of extreme weather events (Safa Imtiaz et al., 2024). In Vidarbha specifically, climate projections indicate significant variability in both maximum and minimum temperatures and precipitation patterns. Rainfall in the first half of the kharif season is anticipated to be deficient, critically affecting rice and soybean during their vegetative phase. Minimum temperatures during the rabi season are projected to rise by approximately 2.5°C relative to current conditions, with adverse consequences for wheat and chickpea yields (Chapke et al., 2017).

Tikadar and Kamble (2023) documented well-defined farmer perceptions of climate change across the region, including observed alterations in rainfall patterns, wind profiles and elevated air temperatures. These changes have directly diminished agricultural productivity, restricted water availability and heightened socio-economic vulnerability. Research consistently links climate-induced yield variability with farmer distress, indebtedness and outmigration. With over 78 percent of Vidarbha's agricultural workforce comprising small and marginal farmers who possess limited adaptive capacity, the region represents one of Maharashtra's most climate-exposed agricultural zones (DES, 2023).

Quantitative assessments of climate impacts on farm income reveal the severity of these vulnerabilities. A rise in temperature of 1°C above normal is associated with a 6.2 percent decline in average farm income during the kharif season and a 6.0 percent decline during the rabi season in unirrigated districts. When rainfall falls 100 mm below the seasonal average, farm incomes decline by 15 percent during kharif and 7 percent during rabi (Economic Survey 2017-18, Government of India). These figures underscore the acute economic exposure of smallholder farmers in Vidarbha to climatic perturbations.

4 GHG Emissions in Agriculture

A diverse portfolio of agricultural practices has been recognised globally for their potential to reduce GHG emissions while simultaneously building climate resilience. Robertson (2004) identified five broad mitigation approaches: (i) energy efficiency improvements in fuel-dependent agricultural operations; (ii) soil carbon sequestration through modified tillage practices; (iii) crop residue and animal waste management combined with cover cropping; (iv) production and utilisation of biofuels and bio-based materials to offset fossil fuel consumption; and (v) optimised livestock and crop yield efficiency to reduce the need for land conversion.

Smith et al. (2008) categorised GHG mitigation potential in agriculture into three pathways: emission reduction, elimination and prevention. Effective regulation of carbon and nitrogen flows within agro ecosystems is identified as central to reducing emission volatility. The Food and Agriculture Organization's (FAO's) climate-smart agriculture (CSA)

framework (FAO, 2013) provides an integrated

approach that addresses food security and climate challenges simultaneously through aligned technical policy and investment mechanisms.

Hoyoung et al. (2021) identified the principal mitigation levers as: optimisation of fertiliser and agrochemical inputs; development of low-carbon production alternatives; reduction of on-farm energy and fuel consumption; and enhancement of soil carbon stocks. Pathak (2013) emphasised that Indian agriculture presents substantial opportunities for mitigation through soil carbon sequestration, land-use management changes and biomass production. Modified crop compositions favouring perennial species or deep-rooted varieties, reduced tillage practices and improved irrigation and fertiliser management are among the strategies identified for simultaneous N_2O and CH_4 reduction (Pathak et al., 2014).

5 Research Gaps Identified

The review of literature systematically identifies four primary knowledge deficiencies that constrain the design and implementation of targeted mitigation and adaptation strategies for Vidarbha's agricultural sector:

SN	Research Gap	Description and Implication
1	**Limited Region-Specific GHG Data**	Absence of disaggregated emissions data across Vidarbha's agro-climatic zones, particularly for key crops (cotton, paddy, soybean). National-level datasets lack the spatial granularity required for targeted local interventions.
2	**No Comparative GHG Tool Analysis**	Multiple IPCC-recognized models exist but remain unevaluated for their relative efficacy in Vidarbha's specific agricultural value chains. Selecting a best-fit tool requires empirical comparative assessment.
3	**Inadequate Climate Risk Mapping**	Limited long-term empirical analysis of temperature and precipitation trends across all 11 districts of Vidarbha. Prior studies rely on farmer perceptions without comprehensive historical climate data analysis.
4	**Absence of Integrated Adaptation–Mitigation Framework**	Strategies such as conservation tillage and agroforestry are documented globally but remain unapplied within specific Vidarbha value chains in an integrated adaptation and mitigation framework.

6. Significance of the Study

6.1 Policy Relevance

The findings of this research will furnish evidence-based insights for policymakers at both state and national levels, supporting the development of sustainable agricultural practices aligned with India's Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement. The study is specifically designed to inform policy frameworks that promote climate-resilient value chains, GHG reduction strategies and the effective dissemination of climate information to smallholder farming communities. It will be particularly valuable for integrating climate adaptation strategies into Maharashtra's agricultural policy architecture.

6.2 Practical Implications

Beyond policy relevance, the study's outcomes

will serve as a practical guide for value chain actors including farmer producer organisations, agribusinesses, processing enterprises and development agencies in implementing climate-smart practices. The research aims to contribute to improved decision-making processes for climate risk management, mainstreaming climate-resilient practices into day-to-day agricultural operations. Additionally, the study will provide actionable recommendations for enhancing the effectiveness of climate agro-advisories, thereby contributing to improved adaptation outcomes for the region's smallholder farming community.

Conclusion

This review establishes the magnitude and complexity of the dual challenge confronting Vidarbha's agricultural sector: escalating climate variability that threatens productivity and livelihoods, and significant GHG emissions from agricultural practices that exacerbate the very climate problem affecting the region. Climate variability characterised by unpredictable monsoon patterns, heightened drought frequency and rising temperatures has profoundly disrupted agricultural output, farmer incomes and the socio-economic fabric of rural communities across Vidarbha's 11 districts.

The review confirms that agrifood systems must simultaneously reduce their GHG contributions and strengthen adaptive capacity objectives that require integrated, holistic strategies rather than isolated interventions. The four research gaps identified in this review-limited region-specific GHG data, absence of comparative GHG tool analysis, inadequate climate risk mapping and lack of integrated adaptation-mitigation frameworks collectively define the scope and rationale for this study. Addressing these gaps is critical for enabling policymakers, development practitioners and value chain actors to implement targeted, evidence- based climate action in Vidarbha.

This review establishes the analytical and contextual foundation for subsequent chapters which will explore the comparative evaluation of GHG estimation tools, the assessment of long-term climate variability impacts and the formulation of pathways for sustainable and climate- resilient agricultural value chains in the Vidarbha region of Maharashtra.

- Ravi N. Parmar
PhD Research Scholar
Savitribai Phule Pune University (SPPU)
Central Research Station under SPPU
BAIF Development Research Foundation
Urulikanchan, District Pune.
Mob. 97237 45487

- Dr. Vitthal Kauthale, Ph.D.
Chief Thematic Programme Executive
BAIF Development Research Foundation
Central Research Station,
Urulikanchan, District Pune.

References:

Carleton, T. A. (2017). Crop-damaging temperatures increase suicide rates in India. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(33), 8746–8751.

Chapke, R. R., Dayakar, B., & Tonapi, V. A. (2017). Role of millets in doubling farmers' income and sustainable development of Vidarbha region of Maharashtra. Proceedings of National Workshop on Doubling Farmers' Income through Scaling Up: KISAN-MITrA, ICRISAT.

Daksh, K., Kumari, V., Kumari, A., Mayoor, M., Singh, H. P., & Mahapatra, S. (2018). Drought risk assessment in Vidarbha region of Maharashtra, India, using Standardized Precipitation Index. International Journal of Innovative Knowledge Concepts, 6(10).

DES. (2024). Economic Survey of Maharashtra 2023–24. Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, Government of Maharashtra, Mumbai.

Dongre, A. R., & Deshmukh, P. R. (2012). Farmers' suicides in the Vidarbha region of Maharashtra, India: A qualitative exploration of their causes. Journal of Injury & Violence Research, 4, 2–6.

FAO. (2023). Emissions totals. In: FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Hoyoung, K., Xinyu, L., Hui, H., & Michael, W. (2021). Principal factors influencing agricultural greenhouse gas emissions and mitigation strategies. Environmental Science & Technology.

Tubiello, F. N., Karl, K., Flammini, A., Gütschow, J., Obli-Laryea, G., Conchedda, G., & Halldórudóttir Heiðarsdóttir, H. W. (2022). Pre- and post-production processes increasingly dominate greenhouse gas emissions from agri-food systems. Earth System Science Data, 14, 1795–1809.

Yuan, X., Li, S., Chen, J., Yu, H., Yang, T., Wang, C., & Ao, X. (2023). Impacts of global climate change on agricultural production: A comprehensive review. Agronomy, 14(7), 1360. https://doi.org/10.3390/agronomy14071360

माँ

माँ–बच्चे की पहली गुरु
चुम्बन से शिक्षा है शुरु

वह आँचल की छाँव तले
समता का ही पाठ पढ़े

लेकिन जब वह बड़ा हुआ
पढ़ा पाठ वह भूल गया

अर्थ मूल्य सब बदल गए
इसको कौन पढ़ाता है

कौन सिखाता है चोरी
क्यों आतंक मचाता है

बहुजन हिताय भूल गया
बहुजन सुखाय भूल गया

सुखमय वातावरण बने
जीवन का व्याकरण बने

हर बालक हो गौतम–सा
या अम्बेडकर जैसा हो

कितना अच्छा हो जाए
यदि धरती पर ऐसा हो

हर बिटिया झलकारी हो
महकी हर फुलवारी हो।

डॉ. तारा परमार
9–बी, इन्द्रपुरी सेठीनगर

दलितों, वंचितों एवं शोषितों की प्रखर आवाज, जनप्रिय बहुजन नेता

कांशीराम जी

की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि

वंचित वर्ग के उत्थान में आपका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स, 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार